PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Bhaskar, Faridabad
Thursday, 5th May 2011, Page: 10
Width: 12.83 cms Height: 14.61 cms, Ref: pmin.2011-05-05.50.73

गरीबों को खिला दीं एक्सपायरी डेट दवाएं

संसद की लोकलेखा समिति की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

एजेंसी | नई दिल्ली

गांवों के गरीब मरीजों को सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गरीबों को लाखों रुपए की ऐसी दवाएं खिला दी गई जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी।

यह खुलासा स्वास्थ्य मंत्रालय की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनी लोकलेखा समिति (पीएसी) की 32वीं रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2005-2012 तक की केंद्र की इस योजना के तहत ओडीशा के गरीब मरीजों को तीन लाख रुपए से ज्यादा मूल्य की एक्सपायरी दवाएं खिला दी गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्य दवा प्रबंधन इकाई ने दवाओं की मियाद खत्म होने की जानकारी देर से दी। इस रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी मरीजों को घटिया दवाएं दी गईं जबकि बिहार में तो दवाओं की गुणवत्ता जांचने का कोई तरीका ही नहीं है। छह राज्यों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाएं, गर्भ निरोधक गोलियां तथा टीके नदारद थे। समिति ने इस पर हैरानी जताई है कि जिन पीएचसी का निरीक्षण किया गया उनमें से 69 में कोई चिकित्सक ही नहीं था।

जननी सुरक्षा योजना के तहत दक्ष दाइयों को प्रसव के लिए विशेष राशि दी जाती है, लेकिन नमूने के रूप में चयनित 25 में से 19 जिलों में घरों में ही होता है प्रसव। मिशन की शुरुआत से अभी तक इसका कोई ऐसा अध्ययन नहीं कराया गया जिससे इसके क्रियान्वयन में कमी का पता लगाकर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। मिशन का लक्ष्य शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी करना था। शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्म पर राष्ट्रीय औसत 60 से 30 पर लाने का लक्ष्य रखा गया था।

आंकड़ों पर एक नजर

15 राज्यों के 11 फीसदी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोई डॉक्टर नहीं।

28 राज्यों के 46 फीसदी केंद्रों में आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति ही नहीं हुई।

10 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य बजट की रखी गई है आयुष चिकित्सा के लिए।

9 राज्यों के 25 आकांक्षी जिलों में से 19 में प्रसव अस्पतालों की जगह घरों में होता मिला।

45776 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर 2009-10 तक खर्च।